2017-18 का बजट और नाबार्ड - सिंचाई

बजट में नाबार्ड को जल के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रु.5,000 करोड़ के अलग आबंटन के साथ-साथ दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के तहत रु.20,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया गया है. फरवरी 2016 में नाबार्ड में एलटीआईएफ के गठन के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को ऋण के रूप में 64 परियोजनाओं में केंद्र सरकार के हिस्से के समक्ष रु.21,488 करोड़ की मंजूरी दी गई है. बाद में नाबार्ड ने गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों को ऋण मंजूर किए. इस तरह, 31 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, एलटीआईएफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा की गई संचयी मंजूरी **रु.35,322** करोड़ हो गई है. इन मंजूरियों से इन परियोजनाओं के अंतर्गत संचयी सिंचित क्षेत्र 46.48 लाख हेक्टे. हो जाएगा.